श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात कर रामराज्य को साकार बनायें- भजनलाल

मुख्यमंत्री रामगंजमंडी में पं.धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में आयोजित रामकथा में शामिल हुए

रामगंजमंडी, 24 जनवरी (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को रामगंजमंडी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में आयोजित रामकथा एवं गौ महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि रामकथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की पाठशाला है। यह हमें बेटे के धर्म, भाई के प्रेम, पति के समर्पण और राजा के कर्तव्य से अवगत कराती है। उन्होंने कहा कि श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रामराज्य की संकल्पना को साकार कर सकेंगे।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सरल और प्रभावशाली वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म का दीपक जलाकर सनातन धर्म को सीधे लोगों के दिल में पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को रामगंजमंडी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में आयोजित रामकथा एवं गौ महोत्सव में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में नदियों, पहाड़ों, वृक्षों और गौ माता को पूजने की परम्परा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें दिव्य रामकथा का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सरल और प्रभावशाली वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म का दीपक जलाकर सनातन धर्म को सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। शास्त्री जी की वाणी में वह सहजता है, जो आम आदमी को छू जाती है। वे युवा पीढ़ी को सनातन धर्म की महानता से परिचित करवा रहे हैं।

इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दुपट्टा ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर व विधायक कल्पना देवी सहित, संत-महंत एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

गुजरात में एसयूवी-ट्रक टक्कर में 6 मरे

बनासकांठा (गुजरात), 24 जनवरी। गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। आबू-पालनपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पार कर एसयूवी से टकरा गया, जिससे छह लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया।

पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना शाम करीब सात बजे इक़बालगढ़ गांव के पास हुई। राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहा ट्रक अचानक नियंत्रण खो बैठा, डिवाइडर कूद गया और सामने से आ रही एसयूवी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। वाहन में सवार लोग संभल भी नहीं पाए। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में कुल नौ लोग सवार थे, जो राजस्थान से इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। तीन घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अमीरगढ़ पुलिस स्टेशन के निरीक्षक पी.डी. गोहिल ने बताया कि ट्रक को मौके पर छोड़ दिया गया है और चालक की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

- **आबू-पालनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर कूद कर एसयूवी से टकराया।**

बिना मान्यता ऑनलाइन मेडिकल टैस्ट कर रही कंपनियों पर कब लगेगी रोक?

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा

- **अदालत ने पूछा कि वर्ष 2020 में जब आदेश दिए जा चुके हैं तो साढ़े 5 साल में भी नियम क्यों नहीं बन पाए?**
- **जयपुर के डॉ. रोहित जैन ने एमेज़ॉन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर और हैदराबाद के 450 पिनकोड एरिया में ऑनलाइन मेडिकल सुविधा देने के प्रकरण को भी अदालत से साझा किया।**

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 24 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि बिना सरकारी मान्यता के ऑनलाइन मेडिकल टैस्ट कैसे बुक किए जा रहे हैं और सरकार इन लैब संचालकों पर क्या कार्रवाई कर रही है? जबकि हाईकोर्ट 6 अगस्त 2020 को ही इस संबंध में कार्रवाई के आदेश दे चुका है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार शपथ पत्र पेश करके बताए कि कब तक इस संबंध में नियम बनाए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि इन नियमों के दायरे में ऑनलाइन मेडिकल टैस्ट की बुकिंग कर रही कंपनियां भी आएंगी अथवा नहीं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई 2026 को रखी है। जस्टिस सचिन दत्ता की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. रोहित जैन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जयपुर निवासी याचिकाकर्ता डॉ. रोहित जैन की ओर से अधिवक्ता शशांक देव सुधी ने अदालत को बताया कि एमेज़ॉन इंडिया द्वारा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर और हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों में 450 पिनकोड एरिया में ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जा रही है। इसके लिए एमेज़ॉन भारत द्वारा नोएडा की ऑरेंज हैल्थ लैब से अनुबंध किया हुआ बताया जा रहा है। परंतु हैरानी की बात यह है कि एमेज़ॉन द्वारा जो मेडिकल जांचें बुक की जा रही हैं, उनकी जो रिपोर्ट जारी होती है, उनमें यह अंकित नहीं होता है कि यह रिपोर्ट किस डॉक्टर ने सत्यापित की है, अथवा नोएडा की जिस लैब से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है, उसका संचालक कौन है? यह जानकारी छिपाना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके बावजूद केन्द्र और दिल्ली सरकार इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, जबकि इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) अथवा नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज़ (एन.ए.बी.एल.) से मान्यता प्राप्त लैब ही वैध रूप से मेडिकल जांच कर सकती है। ऐसे में एमेज़ॉन और ऑरेंज हैल्थ लैब की मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता पर भी संदेह है। यह आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा है।

इस प्रकरण में दिल्ली सरकार ने नियमावली बनाने के लिए अदालत से समय मांगा और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के वर्ष 2020 के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही मजबूत कानून बनानकर ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे गैरकानूनी मेडिकल लैब पर कार्रवाई की जा सके। इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार शपथ पत्र पेश करके बताए कि आखिर कब तक इस संबंध में नियम बना लिए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि इन नियमों के दायरे में ऑनलाइन मेडिकल टैस्ट की बुकिंग कर रही कंपनियां भी आएंगी अथवा नहीं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई 2026 को रखी है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में गत 20 जनवरी को सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि इन ऑनलाइन मेडिकल लैब संचालकों, जिन्हें भारत सरकार की किसी भी संस्था या विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है, पर कार्रवाई करने के लिए 6 अगस्त 2020 को आदेश दिए गए थे, जिसमें साफ कहा था कि दिल्ली सरकार "क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट 2010" की पालना करे और इन अवैध लैबों पर कार्रवाई करें।

डॉ. रोहित जैन की ओर से अदालत में बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के 5 साल बाद भी दिल्ली सरकार इन फर्जी ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कदम नहीं उठा पायी। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2025 में "एमेज़ॉन भारत" ने भी तथाकथित "ऑरेंज हैल्थ लैब" के साथ मिलकर ऑनलाइन मेडिकल टैस्ट की सुविधा देश के कई महानगरों में शुरु कर दी। हैरानी की बात है कि एमेज़ॉन इंडिया दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर और हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों में 450 पिनकोड एरिया में यह सुविधा देने का दावा कर रही है। परंतु सवाल यह उठता है कि कई शहरों की मेडिकल जांच के सैंपल आखिर एक ही लैब से किस प्रकार टैस्ट कर रिपोर्ट जारी की जा रही है। इतनी भारी संख्या में मेडिकल जांच करना किसी एकमात्र लैब के लिए संभव ही नहीं है। दूसरी ओर एमेज़ॉन इंडिया ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जिसे मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी निजी जानकारी मिल रही है, जिसे वह अन्य मेडिकल संस्थाओं को बेच सकता है।

पुरानों पर संदेह है और नयों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले साल अक्टूबर में ही शी जिनपिंग ने सी.एम.सी. के अन्य वरिष्ठ जनरलों को "गंभीर कदाचार" के आरोपों में बर्खास्त कर दिया था। आमतौर पर इन आरोपों का मतलब भ्रष्टाचार होता है। ऐसे मामलों में आरोपित अधिकारियों को अपनी सफाई देने का लगभग कोई मौका नहीं मिलता और उन्हें सभी आरोप स्वीकार कर सार्वजनिक रूप से अपने आचरण की निंदा करनी पड़ती है।

चीन के पुनरुत्थान के सूत्रधार देंग शियाओपिंग को भी माओ त्से तुंग के दौर में बार-बार ऐसे ही आरोपों का सामना करना पड़ा था। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान और उसके बाद माओ के अस्थिर रवैये के कारण देंग को भारी अपमान सहना पड़ा। माओ की मृत्यु के बाद ही उनका पुनर्वास हो सका।

जनरल झांग पर भी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। उनके भविष्य को लेकर अफवाहें तब तेज हो गई थीं, जब वे जनरल ल्यू झेनली के साथ कई पार्टी कार्यक्रमों और शीर्ष सैन्य बैठकों में नजर नहीं आए।

जनरल ल्यू झेनली भी शीर्ष स्तर के सैन्य नेता थे और सेना के कुछ सबसे संवेदनशील कमांड क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते थे। ये सभी कार्रवाहियाँ पिछले साल अक्टूबर में नौ शीर्ष सैन्य कमांडरों को बाहर किए जाने के बाद हुईं।

इतने बड़े पैमाने पर वरिष्ठ सैन्य नेताओं के अचानक हटने से चीन की सैन्य कमान संरचना में बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। इनमें जनरल झांग को सबसे अहम माना जाता था, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में उनके पास वास्तविक सैन्य अनुभव सबसे अधिक था।

जनरल झांग को सैन्य ढ ांचे में दूसरे नंबर का अधिकारी माना जाता था, क्योंकि वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष थे। इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और अब केवल एक और सदस्य ही बचा है।

चीनी सैन्य व्यवस्था को समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि सेना के शीर्ष स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार मौजूद है। साथ ही, सेना हमेशा सत्ता संघर्ष का सबसे अहम केन्द्र भी रही है। जिस नेता के पास सेना का नियंत्रण होता है, वही सत्ता में बने रहने की उम्मीद कर सकता है।

अपने समय में देंग शियाओपिंग ने भी इसी तरीके से सत्ता बनाए रखी थी, और आज शी जिनपिंग भी वही कर रहे हैं। हालांकि माओ इतने शक्तिशाली थे कि सेना पर पकड़ होने के बावजूद वे देंग को हटाने में सफल रहे।

पर्यवेक्षकों का मानना है कि अब राष्ट्रपति शी ने ऐसा व्यापक नियंत्रण तंत्र खड़ा कर लिया है कि वे लगातार सैन्य सफाए के बावजूद, सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सकते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने का उनका अभियान इस लक्ष्य को हासिल करने का एक प्रभावी साधन बन गया है।

फिर भी, शी जिनपिंग ने चीनी प्रशासन और राज्य व्यवस्था के बड़े हिस्से को अपने से दूर कर लिया है। वे अब लगातार अपने वफादार गुट पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे सक्षम और प्रभावी लोगों को निकलने की स्थिति और ज्यादा बन रही है।

इन शीर्ष विशेषज्ञों को हटाने और उनकी विशेषज्ञता खोने से सरकारी व्यवस्था और कमजोर होती जा रही है। स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि शी जिनपिंग अब शीर्ष पदों पर खाली जगह भरने के लिए नए लोगों की नियुक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं।

इसका मुख्य कारण यह है कि शी अपने सबसे करीबी भरोसेमंद लोगों को भी खोते जा रहे हैं और उन्हें नए लोगों की निष्ठा पर संदेह होने लगा है। जनरल झांग, हटाए जाने से पहले तक, सीएमसी के उपाध्यक्ष के रूप में शी जिनपिंग के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते थे। उन्हें स्वयं शी ने नियुक्त किया था और अचानक हटाए जाने तक वे सैकंड इन कमांड बने रहे।

जनरल झांग और राष्ट्रपति शी एक ही तरह की पृष्ठभूमि से आए थे, जिससे झांग को उनका भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। जनरल झांग के पिता माओ के शासनकाल में एक सफल सैन्य कमांडर थे, लेकिन बाद में उन्हें भी वही सफाया झेलना पड़ा, जो राष्ट्रपति शी के पिता को सहना पड़ा था। बाद में दोनों का आंशिक पुनर्वास हुआ।

इस तरह शी और झांग दोनों ही चीनी सामाजिक ढ ांचे के तथाकथित "राजकुमार" थे और उन्होंने काफी हद तक एक जैसे करियर रास्ते अपनाए।

यह लगभग तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अपनी राज्य व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर, खासकर सैन्य ढ ांचे में, गंभीर नेतृत्व संकट का सामना कर रहे हैं।

वर्षा के बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब माना जाता है।

भारत से 25 प्रतिशत टैक्स हटा सकता है अमेरिका

वॉशिंगटन डीसी, 24 जनवरी। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से आयात करना कम कर दिया है, जिसके चलते जल्द ही 25 फीसदी टैरिफ हटाया जा सकता है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और कहा कि भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत टैरिफ काफी असरदार रहा है और इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घट गई है। बेसेंट ने पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में बताया, भारत पर टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी की है, जिससे भारत ने ट्रंप सरकार को इस टैरिफ पर विचार करने का मौका दिया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के बाद भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। अमेरिका ने उस समय बताया था कि भारतीय रिफाइनरियों ने डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल की खरीदारी काफी बढ़ा दी, लेकिन देखा जाए तो अब ये खरीदारी पूरी तरह से बंद हो गई है। बेसेंट ने आगे कहा, भारत ने अब जब रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है तो अमेरिका भी टैरिफ हटाने पर विचार कर सकता है। स्कॉट बेसेंट ने भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों पर पड़े असर को अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की सफलता बताया।

थरूर ने कैनडा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया, जो औपचारिक कूटनीति तो कम, एक स्पष्ट चेतावनी ज़्यादा था। मूल रूप से उन्होंने एक ऐसा 'सर्वाइवल मैनुअल' पेश किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी।

कैनडा के प्रधानमंत्री कार्नी, जो लंदन और ओटावा के केन्द्रीय बैंकिंग बोर्डरूम से निकलकर एक जी7 देश के नेतृत्व तक पहुंचे हैं, ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए वैश्विक व्यवस्था में किसी साधारण बदलाव के बजाय, एक गहरी टूटन की बात कही। थरूर ने कहा कि कार्नी ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंत की घोषणा की और चेतावनी दी कि थ्यूसीडाइड्स की प्रसिद्ध उक्ति , ताक़तवर जो कर सकता है, वह करता है, और कमज़ोर वही सहता है, जो उसे सहना पड़ता है, अब कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं, बल्कि हमारी मौजूदा वास्तविकता है।

थरूर ने कहा कि भारतीय श्रोताओं के लिए कार्नी का विश्लेषण जाना पहचाना है, हालांकि बेचैन करने वाली, स्पष्टता से भरा हुआ है। थरूर ने उन्होंने कहा, जब हम 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, तो वह वैश्विक ढांचा, जिस पर हमने व्यापार और सुरक्षा के लिए भरोसा किया था और जिसने दुनिया में हमारी भूमिका को परिभाषित किया, राष्ट्रपति ट्रंप की महाशक्ति-आधारित लेन-देन की नीति द्वारा सुनियोजित रूप से तोड़ा जा रहा है। हमें भी स्थिति को लेकर उतनी ही ईमानदारी दिखानी होगी, जितनी कार्नी ने अपने भाषण में दिखाई।

राहुल भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सलाह देते और निर्णय लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान में कोई वरिष्ठ नेता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, और राज्यों से बुलाए गए नए नेता अनुभवहीन हैं।

ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पार्टी को उन लोगों के हाथ में छोड़कर खुश हैं, जिनके पास न तो राजनीतिक अनुभव है और न ही वर्तमान गला काट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समझने की क्षमता है, जिसमें कांग्रेस का मुकाबला भाजपा और उसकी संगठित राजनैतिक व चुनावी मशीनरी से है।

अतीत के पार्टी स्तंभ अब गायब हैं और राज्यवार फोटो लाइनअप में केवल नए चेहरों को देखा जा सकता है, जिनके पास अनुभव नगण्य है।

'बिहार चुनाव में कई सीटों पर टिकट बेचे गए'

- **राजद के विधायक भाई वीरेन्द्र ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए**

पटना, 24 जनवरी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक भाई वीरेन्द्र ने शनिवार को अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने प्रभाव से टिकट बेचे, जिसके कारण राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा।

वीरेन्द्र ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए गहन जांच की जानी चाहिए।

राजद विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ पार्टी नेताओं की संदिग्ध भूमिका के कारण राजद ने चुनाव में वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया। उन्होंने बताया कि एक वरिष्ठ नेता के पास तीन जिलों रोहतास, कैमूर और बक्सर की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनका व्यवहार, आचरण और सिद्धांत समाजवादी भावना के अनुकूल नहीं था।

राजद विधायक ने कहा कि एक खास नेता टिकट आवंटन में गलत उम्मीदवारों के चयन के लिए जिम्मेदार थे, जिसके कारण राजद का प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने पार्टी से मांग की कि ऐसे नेताओं को बेनकाब करने के लिए गहन जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजद के पूर्व विधायक और एक ईमानदार एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्ता विजय मंडल को गलत चयन के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट नहीं दिया गया। इस बीच राजद विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनके आरोपों से यह आशंका अब सच में तब्दील हो गई है कि राजद में टिकट बेचे गए। उन्होंने कहा कि यही कारण था कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार झेलनी पड़ी। गौरतलब है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को केवल 25 सीटें मिली थीं, जो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती गई 75 सीटों की तुलना में भारी गिरावट है।

जो मुद्दे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के साथ उठाना है, न कि किसी सार्वजनिक मंच पर।" उन्होंने यह भी कहा कि वे संसद सत्र के लिए दिल्ली जाएंगे, जहां उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ एक उचित और सुव्यवस्थित बातचीत का अवसर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं पिछले 17 वर्षों से कांग्रेस में हूं। जो भी गलत हुआ है, उसे संबोधित किया जाना चाहिए और सही मंच पर किया जाएगा।"

ट्रम्प के "ग़ाज़ा स्ट्रिप प्लान" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकी अधिकारियों ने असामान्य रूप से कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि अमेरिका इज़रायल की आपत्तियों की परवाह किए बिना इस ढांचे के साथ आगे बढ़ेगा। संदेश साफ था: अमेरिकी धैर्य कम हो रहा है, और नेतन्याहू सरकार के साथ स्वत:स्फूर्त रणनीतिक तालमेल का दौर खत्म हो चुका है।

यह प्रकरण ट्रंप के वाइट हाउस की गठबंधनों को लेकर बदलती सोच को दर्शाता है। ट्रंप ने कभी भी अपनी लेन-देन आधारित विदेश नीति को छिपाया नहीं है। नाटो से लेकर पूर्वी एशिया तक, वे बार-बार संकेत देते रहे हैं कि गठबंधन पवित्र प्रतिबद्धताएं नहीं, बल्कि उपकरण हैं। इस दृष्टिकोण में, इज़रायल-जिसे ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी विदेश नीति में लगभग अपवाद माना जाता रहा है-भी तब दबाव से मुक्त नहीं है जब अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताएं अलग दिशा में जा रही हैं।

ग़ाज़ा को लेकर वॉशिंगटन की योजना कई परस्पर जुड़ी मजबूरियों से प्रेरित है। पहला, अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय दबाव है कि वह ग़ाज़ा के लिए एक विश्वसनीय शासन-मार्ग प्रस्तुत करे जब बड़े सैन्य अभियान समाप्त हों। दूसरा, वॉशिंगटन ऐसी क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी चाहता है जो धन, प्रशासनिक क्षमता और कूटनीतिक समर्थन दे सकें, जो निकट भविष्य में न तो इज़रायल और न ही फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण अकेले प्रदान कर सकते हैं। क़तर के पास धन है और वह हमास को भी प्रभावित करता है, तुर्की क्षेत्रीय प्रभाव और मुस्लिम दुनिया में पकड़ रखता है। अमेरिकी दृष्टि से, उन्हें बाहर रखना इज़रायल के लिए राजनीतिक रूप से आरामदेह हो सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से अव्यावहारिक है।

नेतन्याहू के लिए, यह योजना उनके राजनीतिक अस्तित्व के मूल पर प्रहार करती है। कोई भी युद्धोत्तर व्यवस्था जो घरेलू स्तर पर इज़रायल की सुरक्षा से समझौता करती दिखे-या इज़रायल के प्रति शत्रुतापूर्ण ताक़तों को सशक्त करती लगे-उनके पहले से नाज़ुक गठबंधन को तोड़ सकती है। वॉशिंगटन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कड़ा रुख अपनाना उन्हें अपने समर्थक आधार के सामने मजबूती का संकेत देने का अवसर भी देता है, ऐसे समय में जब देश के भीतर उनका नेतृत्व सवालों के घेरे में है।

तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप इतने खुले तौर पर आगे बढ़कर सहयोगियों को खोने का जोखिम उठा रहे हैं?

इसका जवाब साधारण हां या ना में नहीं है। ट्रंप के कारण इज़रायल को पारंपरिक अर्थों में "खोना" अमेरिका के लिए संभव नहीं दिखता। सैन्य सहयोग, खुफिया साझेदारी और गहरे संस्थागत रिश्ते बरकरार हैं, और इज़रायल के पास अमेरिकी समर्थन के व्यवहारिक विकल्प बहुत कम हैं। लेकिन जो स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ रहा है, वह है बिना सवाल के रणनीतिक तालमेल की धारणा। सहयोगियों को अब यह संदेश मिल रहा है कि असहमति वॉशिंगटन को कदम उठाने से नहीं रोकेगी-और यह संदेश इज़रायल से कहीं आगे तक गूंज रहा है। यूरोप में भी सुरक्षा और व्यापार पर अमेरिकी अनिश्चितता को लेकर इसी तरह की चिंताएं उभरी हैं। मध्य पूर्व में साझेदार अपने विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, संतुलन बना रहे हैं और संबंधों में विविधता ला रहे हैं। ग़ाज़ा विवाद इस बढ़ती धारणा को मजबूत करता है कि ट्रंप के तहत अमेरिकी नीति दीर्घकालिक गठबंधन प्रबंधन के बजाय अल्पकालिक दबाव को प्राथमिकता देती है।

वॉशिंगटन के लिए इस दृष्टिकोण में जोखिम हैं। सहयोगी सामरिक रूप से तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ चुपचाप अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। एक बार भरोसा कमज़ोर पड़ जाए, तो उसे बहाल करना कठिन होता है-और सार्वजनिक टकराव उस क्षरण को और भी स्पष्ट कर देते हैं।

फिर भी ट्रंप के दृष्टिकोण से यह गणना जानबूझकर की गई लगती है। वे गठबंधनों में तनाव स्वीकार करने को तैयार दिखते हैं, यदि इससे अमेरिका बातचीत को लंबा खींचने के बजाय परिणाम थोप सके। ग़ाज़ा के मामले में वाइट हाउस को लगता है कि देरी और अत्यधिक रियायतें केवल अस्थिरता को बढ़ाएंगी-भले ही इसके लिए इज़रायल की आपत्तियों को दरकिनार करना पड़े।

ग़ाज़ा निगरानी बोर्ड सफल होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह प्रकरण एक मोड़ ज़रूर दर्शाता है: अमेरिका-इज़रायल संबंध अब स्वत:संचालित मोड में नहीं हैं। और यही बदलाव, जो योजना से अधिक है, वह बात है जिसे दुनिया भर के सहयोगी सबसे ध्यान से देख रहे हैं।

गणतंत्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह ऐतिहासिक संयुक्त निमंत्रण एक मजबूत कूटनीतिक पहल का संकेत देता है और साथ ही यूरोपीय यूनियन (ईयू) को एकीकृत रणनीतिक साझेदार के रूप में नई दिल्ली की भागीदारी में बड़े बदलाव को दर्शाता है। यह कदम अहम व्यापार वार्ताओं से पहले भारत और ईयू के बीच मजबूत होते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है।

यह पहला अवसर है, जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है, जो ब्रसेल्स के साथ नई दिल्ली के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

यह निमंत्रण कई मायनों में ऐतिहासिक है। बीते दशकों में भारत ने कई नेताओं की मेजबानी की है, लेकिन यह पहला अवसर है, जब यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सामूहिक रूप से ईयू के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे।

भारत ने 1950 से अब तक प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में केवल एक ही नेता को आमंत्रित किया है। ज्ञातव्य है कि 1952, 1953, 1966 और 2022 में किसी अतिथि को आमन्त्रित नहीं किया।

'10 साल में ए.आई. के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जाए, तो ए.आई. हेल्थकेयर को रिएक्टिव ट्रीटमेंट से प्रिवेंटिव केयर में बदलने में मदद कर सकता है, जिससे लागत को नियंत्रित करते हुए परिणाम बेहतर होंगे।

फाइनेंशियल सर्विसेज़ में, ए.आई. से क्रेडिट तक पहुंच आसान हो सकती है, जोखिम मूल्यांकन में सुधार और पर्सनलाइज़्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का विस्तार होने की उम्मीद है, खासकर उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए, जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं कम हैं। इस बीच, रिटेल में स्मार्ट सप्लाई चेन, मांग पूर्वानुमान और हाइपर-पर्सनलाइज़्ड कस्टमर एंगेजमेंट के माध्यम से लाभ देखा जा सकता है, जिससे दक्षता और खपत दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

पी.डब्ल्यु.सी. के फ्रेमवर्क का जोर खासियत ए.आई. को शामिल करने पर है। फर्म का कहना है कि भारत की ताकतें, उसके विशाल और अलग-अलग तरह के डेटा सेट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आधार, यू.पी.आई. और इंडिया स्टैक, और टेक टैलेंट का बड़ा पूल, देश को ऐसी ए.आई. प्रणालियाँ बनाने में सक्षम बनाती हैं, जो अलग-अलग भाषाओं, साक्षरता स्तरों और आय वर्गों के लिए काम कर सकें। अगर भारत इसे सही तरीके से करता है, तो यह दुनिया को ए.आई. डेवलपमेंट का एक काउंटर-मॉडल दे सकता है, जिस पर अभी कुछ विकसित देशों और बड़ी टैक कंपनियों का दबदबा है।

पी.डब्ल्यु.सी. यह भी चेतावनी देता है कि 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इस अवसर को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए डिजिटल और भौतिक ढांचे में लगातार निवेश, बड़े पैमाने पर कौशल प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, मज़बूत डेटा गवर्नेंस व्यवस्था और नैतिक और ज़िम्मेदार ए.आई. इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियम आवश्यक हैं। इनके बिना, ए.आई. साझा समृद्धि का जरिया बनने के बजाय असमानता का एक और स्रोत बन सकता है।

सबसे ज़रूरी बात, कंपनी की रिपोर्ट ए.आई. को इंसानी श्रम के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑग्मेंटेशन टूल के रूप में देखती है, एक ऐसा टूल, जो भारत जैसी श्रम-प्रधान अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ा सकता है, न कि उसे खत्म कर सकता है। पी.डब्ल्यु.सी. का तर्क है कि यहीं भारत के वैश्विक नेतृत्व का अवसर छिपा है, यह दिखाना कि ए.आई. को आबादी के बड़े पैमाने पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि, साथ ही साथ यह किफायती हो, सुलभ हो और सामाजिक रूप से जुड़ा रहे।

जैसे-जैसे देश अपनी ए.आई. रणनीतियों को परिभाषित करने की होड़ में हैं, पी.डब्ल्यु.सी. का आकलन बताता है कि भारत के सामने अब यह चुनौती नहीं है कि वह ए.आई. अपनाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह इसे कैसे करेगा। अगर इसे समावेशन, गवर्नेंस और पैमाने के साथ जोड़ा जाए, तो ए.आई. न सिर्फ विकास को गति देने वाला बन सकता है, बल्कि अगले दशक में भारत की आर्थिक कहानी का एक निर्णायक स्तंभ भी बन सकता है।

वंदे मातरम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शक्तिशाली उद्घोष बना था। अब सरकार इसे उस स्थिति में पुनः स्थापित करना चाहती है, जिसे वह राष्ट्रीय गौरव का मूल स्वरूप मानती है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908